मुख्यमंत्री भजनलाल दस नगर निगमों में रोड शो करेंगे

भाजपा में संगठन स्तर पर मुख्यमंत्री के रोड शो के कार्यक्रम और रूट के बारे में मंथन किया जा रहा है

जयपुर, 3 सितम्बर। राजस्थान में नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने अब चुनाव प्रचार को धार देने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रचार अभियान के प्रमुख चेहरे के रुप में मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी 10 नगर निगम क्षेत्रों में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे।

मुख्यमंत्री शर्मा एक दिन में करीब तीन नगर निगम क्षेत्रों में रोड शो करेंगे और अधिक से अधिक वार्डों में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के साथ पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे। मुख्यमंत्री के रोड शो के लिए भाजपा संगठन स्तर पर कार्यक्रम और रूट तय करने की कवायद शुरू हो गई है।

निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद अब पार्टी का फोकस चुनाव प्रचार और संगठन को पूरी तरह सक्रिय करने पर है। भाजपा नेतृत्व का प्रयास है कि मुख्यमंत्री के रोड शो के जरिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट किया जाए। मुख्यमंत्री के रोड शो प्रदेश के प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में भाजपा के चुनाव अभियान का मुख्य आकर्षण होंगे। भाजपा संगठन मुख्यमंत्री के रोड शो के जरिए एक साथ कई वार्डों में चुनावी प्रभाव पैदा करने की तैयारी कर रहा है। एक दिन में तीन नगर निगमों में कार्यक्रम होंगे, जिससे सीमित समय में व्यापक क्षेत्र को कवर किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- निकाय चुनावों में भाजपा की रणनीति है कि मुख्यमंत्री के रोड शो के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश और जनता में समर्थन हासिल किया जाए। एक दिन में मुख्यमंत्री के तीन नगर निगमों में कार्यक्रम होंगे, जिससे सीमित समय में व्यापक क्षेत्र को कवर किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री के रोड शो के अलावा, पार्टी के प्रदेश और केन्द्रीय स्तर के नेता भी अलग-अलग नगर निगम क्षेत्रों में प्रचार करेंगे।

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के तीन अधिकारी एपीओ

जयपुर, 3 सितम्बर। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघ के हमले में महिला मजदूर की मौत के एक दिन बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेंज अधिकारी गौरव कुमार, सहायक वनपाल प्रदीप कुमार और एनक्लोजर प्रभारी सोनू मीणा को एपीओ कर दिया।

- बाघ के हमले की घटना से पार्क की सुरक्षा व्यवस्था व अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

घटना के बाद पार्क की सुरक्षा व्यवस्था और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे।

वन विभाग ने रेंज अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज जोगेन्द्र सिंह शेखावत को सौंपा है। सहायक वनपाल प्रदीप कुमार की जगह राजाराम और एनक्लोजर प्रभारी सोनू मीणा के स्थान पर सीताराम को जिम्मेदारी दी गई है।

गौरतलब है कि 2 सितंबर को पार्क के एक एनक्लोजर में घास की सफाई के दौरान बाघ ने महिला मजदूर पर हमला कर दिया था तथा गंभीर रूप से घायल महिला की मौत हो गई थी। प्रारंभिक कार्रवाई के तौर पर तीन अधिकारियों को एपीओ किया गया है।

'जब भारत को प्रतिस्पर्धी देशों पर तरजीह मिलेगी, तब ही यू.एस. के साथ ट्रेड एग्रीमैंट घोषित होगा'

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह घोषणा की, साथ ही कहा कि बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमैंट पर वार्ता जारी रहेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 सितम्बर। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि जब वॉशिंगटन अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत को खाज टैरिफ दरें देने पर सहमत हो जाएगा तब भारत अमेरिका के साथ अपने बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमैंट (बी.टी.ए.) की डीटेल्स को अंतिम रूप देगा और इसकी घोषणा करेगा।

- पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब तक जिन व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दे चुका है, उनसे भारतीय कारोबारों को निर्यात के बड़े अवसर मिल रहे हैं।

गोयल ने "एफटीए का लाभ उठाने "लैवरेजिंग एफ टी एज़) पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, "जैसे ही अमेरिका हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में हमें खार दरें देने में सक्षम होगा, हम बीटीए को अंतिम रूप देंगे और इसका पूरा विवरण घोषित करेंगे।"

गोयल ने कहा कि भारत जिन व्यापार समझौतों को पहले ही अंतिम रूप दे चुका है, वे भारतीय कारोबारों के लिए निर्यात के बड़े अवसर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले महीनों और वर्षों में कई और व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने की दिशा में भी काम कर रहा है।

संभावित व्यापार भागीदारों के रूप में जिन देशों पर विचार किया जा रहा है, उनमें कैनडा, मैक्सिको, चिली, ब्राज़ील के नेतृत्व वाला मर्कोसुर ब्लॉक, दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एस.ए.सी.यू.), छह सदस्यीय खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और इज़रायल शामिल हैं।

भारत और अमेरिका आपसी लाभ वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। 22 से 24 जून तक नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, राजदूत जैमीसन ग्रीयर और गोयल ने प्रस्तावित समझौते के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की।

इनमें बाजार तक अधिक पहुंच, डिजिटल व्यापार, मजबूत सप्लाई चेन, गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग शामिल था।

दोनों पक्षों ने कहा कि उनकी बातचीत करने वाली टीमों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है।

उन्होंने एक संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों श्रमिकों और उपभोक्ताओं को ठोस लाभ मिलेगा। फरवरी में भारत और अमेरिका ने आपसी लाभ वाले व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की, साथ ही व्यापक बी.टी.ए. पर बातचीत जारी करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

जून में हुए ताजा घटनाक्रम में ग्रीयर के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने गोयल से मुलाकात के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। दोनों पक्षों ने बीटीए के मुख्य मुद्दों की समीक्षा की और अंतरिम समझौते पर बातचीत जारी रखी।

2025 में अमेरिका को भारत का कुल वस्तु निर्यात 103.82 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि अमेरिका से भारत को वस्तुओं का निर्यात लगभग 45.6 अरब डॉलर था। दोनों देशों के बीच कुल वस्तु व्यापार 149.42 अरब डॉलर रहा।

सेवाओं के क्षेत्र में 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार 92.23 अरब डॉलर रहा। भारत ने अमेरिका को 48.67 अरब डॉलर की सेवाओं का निर्यात किया और 43.56 अरब डॉलर की सेवाओं का आयात किया।

ट्रंप की तस्वीर वाला एक डॉलर का सिक्का जारी

वॉशिंगटन, 03 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नाम से 1 डॉलर का सिक्का जारी किया गया है। यूएस मिंट ने यह सिक्का अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौके पर जारी किया है। इस सिक्के पर ट्रंप की तस्वीर के साथ "लिबर्टी" (आजादी) और "इन गॉड वी ट्रस्ट" (ईश्वर में हमारी आस्था) शब्द लिखे हैं। अमेरिका में ट्रंप के इस कदम को, अमेरिकी संस्थानों पर अपनी छाप छोड़ने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर अमेरिकी डॉलर पर छपी है।

- पहली बार किसी जीवित राष्ट्रपति की फोटो डॉलर पर छपी है।

यूएस मिंट ने कहा कि ये सिक्के आम चलन (सर्कुलेशन) में नहीं लाए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें कानूनी मुद्रा (लीगल टेंडर) के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। संघीय कानून के तहत किसी जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर अमेरिकी करेंसी पर छापने की मनाही है। हालांकि, दलील दी गई है कि यह सिक्का अमेरिका की 250वीं सालगिरह के लिए खास तौर पर जारी किया गया है और यह आम चलन में नहीं आएगी।

लॉ के छात्रों को सज़ा देने का बार काउन्सिल्स को कोई हक नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी हैदराबाद की नलसार लॉ युनिवर्सिटी के छात्रों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 सितम्बर। कानून के छात्रों के लिए बड़ी राहत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए एक झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बार काउंसिल को कानून के छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह महत्वपूर्ण टिप्पणी एनएएलएसएआर (नलसार) लॉ यूनिवर्सिटी मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले छात्रों के खिलाफ आदेश जारी किया था और बाद में उसे वापस ले लिया था।

- नलसार लॉ युनिवर्सिटी के छात्रों ने दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध किया था, जिससे कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था।
- उसके बाद बार काउन्सिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने इन छात्रों के बार में पंजीकरण पर रोक लगा दी थी। हालांकि, उन्होंने आदेश वापस लेकर छात्रों से माफी मांगी थी। पर, दो छात्रों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और राज्य बार काउंसिलों के पास कानून के छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का वैधानिक अधिकार नहीं है।

अदालत ने कहा कि किसी कानून स्नातक के खिलाफ बार काउंसिल को अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार तभी मिलता है, जब वह अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हो जाता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि कानून के छात्रों के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार उनके संबंधित शैक्षिणक संस्थान या उस संस्थान के नियमों और उपनियमों के तहत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के पास होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 अगस्त को बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा जारी निर्देश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किए गए थे। बीसीआई के आदेश में हैदराबाद स्थित एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के छात्रों का नामांकन रोकने और सीजेआई के खिलाफ कथित अभियान को लेकर छात्रों तथा शिक्षकों के खिलाफ जांच शुरू करने को कहा गया था।

विरोध और नाराज़गी के बाद, बीसीआई अध्यक्ष ने आदेश जारी करने के करीब एक घंटे के भीतर ही इन निर्देशों को वापस ले लिया था। बाद में उन्होंने वापस लिए गए आदेश के लिए छात्रों से माफी भी मांगी थी।

एनएएलएसएआर के दो पूर्व छात्र, मिहिर सूद और अभिषेक तिवारी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का पहुँच गये थे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने दलील दी कि भले ही आदेश वापस ले लिए गए हों, लेकिन यह जांचना जरूरी है कि बीसीआई अध्यक्ष ने किस अधिकार और किस कानूनी प्रावधान के तहत ये निर्देश जारी किए थे।

मनन कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि संबंधित निर्देश तुरंत वापस ले लिए गए हैं और बीसीआई की बैठक के बाद यह मामला बंद कर दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की दलील से सहमति जताते हुए कहा कि बीसीआई के पास कानून के छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।

खड़गे ने नड्डा को शुद्धिकरण मामले में उनका आश्वासन याद दिलाया

नई दिल्ली, 03 सितंबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी जनसभा स्थल के तथाकथित 'शुद्धिकरण' मामले में 24 दिन बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर उत्तराखंड सरकार को निर्देश देकर मामले में शामिल लोगों और संगठनों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

- कांग्रेस अध्यक्ष ने नड्डा को लिखे पत्र में कहा कि इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद भी हल्द्वानी पुलिस प्रशासन की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाना निराशाजनक है।

खड़गे ने बुधवार को नड्डा को लिखे पत्र में 13 अगस्त को राज्यसभा में हुई चर्चा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त 2026 को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में उनकी जनसभा के बाद कुछ संगठनों की ओर से कथित तौर पर छुआछूत आधारित शुद्धिकरण कराया गया था। उस समय नड्डा ने सदन में घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। राज्यसभा के सभापति ने भी घटना पर खेद जताया था। खड़गे ने पत्र में नड्डा के सदन में दिए आश्वासन का हवाला देते हुए कहा कि इतने स्पष्ट आश्वासन के बावजूद, हल्द्वानी पुलिस-प्रशासन की ओर से अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाना निराशाजनक और हैरान करने वाला है। उन्होंने नड्डा से अपने आश्वासन के अनुरूप उत्तराखंड सरकार को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि रामलीला मैदान के स्थल का तथाकथित शुद्धिकरण कराया जाना भारतीय संविधान की मूल भावना और मानवीय मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने इसे छुआछूत और जातिवादी मानसिकता से जुड़ा बताया।

तिब्बत में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्षेत्र में दर्ज किया गया। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने के बाद तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस हुए थे, इसके बाद तिब्बत को बाढ़ की मार झेलनी पड़ी है। चीन सीमा से जुड़े इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिली है। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास आई भीषण बाढ़ के बाद तिब्बत में करीब 100 नेपाली नागरिकों के लापता होने की खबर है।

दिल्ली के युवा नेताओं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह मामला हाल ही में प्रखर गुप्ता द्वारा आयोजित एक पॉडकास्ट के बाद फिर सामने आया, जिसमें वे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ बातचीत कर रहे थे।

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही पॉडकास्ट की एक कथित क्लिप में गुप्ता एक करीबी दोस्त के बारे में चर्चा करते दिखाई देते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उसने बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और दीपके की सीजेपी से जुड़े प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था।

प्रसारित क्लिप के अनुसार, गुप्ता ने कहा, बोस्टन यूनिवर्सिटी अभिजीत का कॉलेज भी है।

गुप्ता ने दावा किया कि उनके दोस्त ने बाद में दीपके की शैक्षिणक योग्यताओं की जांच पड़ताल की और कथित तौर पर पाया कि विश्वविद्यालय से उनके स्नातक होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

गुप्ता ने दावा किया, "एक महीने बाद वे अभिजीत की शैक्षिणक योग्यता की जांच में पूरी तरह जुट गए और उन्होंने पाया कि बोस्टन यूनिवर्सिटी से उनके स्नातक होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है।"

ये पॉडकास्ट में किए गए दावे हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की गई है।

दीपके पहले भी यह कहते रहे हैं कि उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और उनकी शिक्षा का खर्च छात्रवृत्ति के जरिए पूरा हुआ था।

दीपके की शिक्षा और, उसका खर्च किस तरह उठाया गया, इसे लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं।

सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने दीपके के पिता भगवानराव दीपके की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की थी। भगवानराव महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। तिवारी ने सवाल उठाया था कि जब दीपके के पिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) में जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, तो परिवार अमेरिका में शिक्षा का खर्च कैसे उठा सकता था।

- इसके बाद दीपके ने जवाबी हमला किया, मेरी डिग्री के बारे में पूछने वाले प्रधानमंत्री की डिग्री पर भी कुछ बोलें, मैं चुनौती देता हूँ, वे प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाएं, मैं अपनी डिग्री दिखा दूंगा।

तिवारी ने मीडिया से कहा, "मैंने महाराष्ट्र सरकार से शिकायत की है कि भगवानराव दीपके एमआईडीसी में जूनियर इंजीनियर थे। अगर उन्हें 60,000-65,000 रुपये वेतन मिलता था, तो वे अमेरिका में अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च कैसे उठा पाए?"

पत्रकार बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में दीपके ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी शिक्षा का खर्च बोस्टन यूनिवर्सिटी की छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण के जरिए उठाया गया था।

दीपके ने कहा, "मेरी शिक्षा का खर्च बोस्टन यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई छात्रवृत्ति से पूरा हुआ था। और मैंने कुछ शिक्षा ऋण भी लिया था, जिसे मुझे अब चुकाना है।"

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वह पत्र भी दिखाया, जिसे उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से मिला अपना छात्रवृत्ति पत्र बताया।

सीजेपी के संस्थापक इससे पहले भी प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के लिए शैक्षिणक डिग्रियों के मुद्दे का इस्तेमाल कर चुके हैं।

एक अन्य एक्स पोस्ट में दीपके ने सवाल उठाया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने से इनकार क्यों किया। साथ ही उन्होंने भाजपा द्वारा शैक्षिणक योग्यताओं की कथित जांच का जिक्र करते हुए व्यंग्य किया।

दीपके ने लिखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने से इनकार क्यों किया? उन्होंने आगे कहा, पिछले कुछ दिनों में आईटी सेल से मैंने जो सीखा है, उसके अनुसार, जो व्यक्ति अपनी डिग्री नहीं दिखाता, वह कथित तौर पर धोखेबाज और झूठा है।

मोदी की शैक्षिणक योग्यताओं को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी वर्षों से सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि यह मुद्दा पहले ही सुलझ चुका है और उसने पहले भी मोदी की डिग्री सार्वजनिक रूप से दिखाई है।

इस बीच, सीजेपी ने दीपके की शिक्षा को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच, उनका बचाव किया है। पार्टी की प्रवक्ता वैष्णवी गौड़ ने भी आरटीआई जांच की आलोचना करते हुए कहा कि किसी निजी व्यक्ति की शिक्षा पर होने वाले खर्च पर सवाल उठाने वालों को "पीएम केयर्स फंड" की भी जांच करनी चाहिए।

भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की गिरफ्तारी से उन्हें और कांग्रेस पार्टी को ही फायदा हो सकता है, इसलिये इस पर भाजपा को सोच-समझकर फैसला करना होगा।

जीडीपी की गणना पर विवाद उठना इकॉनमी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है

जीडीपी की गणना कैसे होती है, यह अब तक स्पष्ट नहीं था, पर इस तरह विवाद उठने से इस प्रक्रिया का खुलासा हो गया है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 सितम्बर। जब एनएसओ (नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस) ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में जीडीपी में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि की खबर दी, तो इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है।

यह कोई नई बात नहीं है। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर विवाद कोई नई या अनोखी बात नहीं है। जब भी बहुत शानदार आंकड़े सामने आते हैं या जब आंकड़ों में कोई बड़ा बदलाव किया जाता है, तब ऐसा विवाद होता है।

राष्ट्रीय आय के आंकड़े तैयार करना एक जटिल काम है और भारत जैसे विशाल देश के लिए यह बहुत बड़े पैमाने पर आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय आय के अनुमानों से जुड़े कई बारीक और तकनीकी पहलू होते हैं। लेकिन आम तौर पर दो मुद्दों पर विवाद होता है।

पहला, ये आंकड़े अपनी प्रकृति के अनुसार, कुछ खास आधारों, यानी "बेस ईयर" के संदर्भ में तैयार किए जाते हैं। बेस ईयर का उपयोग प्राइस इंडैक्स (कीमत सूचकांक), मैन्युफैक्चरिंग इंडैक्स या कुल राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को तैयार करने में किया जाता है।

- जीडीपी के आंकड़े बेस ईयर के संदर्भ में तैयार होते हैं और इन आंकड़ों की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बेस ईयर को अपडेट किया जाता है। क्योंकि, जब अर्थव्यवस्था में बदलाव आता है तो इसके मुख्य तत्वों खपत और उत्पादन आदि में भी बदलाव होता है।

समय के साथ इन आंकड़ों की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बेस ईयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। तुलना को सही और उचित बनाने के लिए इन्हें आगे के वर्षों में ले जाया जाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बदलाव आता रहता है और इसके सभी प्रमुख तत्व भी बदलते रहते हैं, जैसे खपत का तरीका, उत्पादित होने वाली वस्तुएं और अन्य महत्वपूर्ण पैमाने।

पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान को लेकर मुख्य विवाद यह है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़े में बदलाव किया गया है। वास्तव में, पिछले वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी अनुमान को 6 लाख करोड़ रुपये तक कम कर दिया गया था। स्वाभाविक रूप से, जब इस वर्ष के आंकड़े की तुलना पिछले वर्ष की पहली तिमाही के कम किए गए आंकड़े से की जाएगी, तो इस वर्ष का अनुमान उतना ही बढ़ जाएगा।

इस बार इस बहस को पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के बयान से और बल मिला। उन्होंने दावा किया कि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़े को संशोधित करके अधिक वृद्धि दर का आंकड़ा गढ़ा गया है। सवाल यह है कि पिछले वर्ष के आंकड़े को क्यों बदला गया या क्यों कम किया गया।

सरकार के अर्थशास्त्रियों ने बताया कि आंकड़ों में यह कमी इसलिए की गई, क्योंकि इस वर्ष फरवरी में जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष (बेस ईयर) को अपडेट किया गया था। पहले बेस ईयर 2011-12 था, जिसे बदलकर 2021-22 कर दिया गया। विभिन्न सूचकांकों (इंडैक्स) और सांख्यिकीय अनुमानों की गणना में यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है।

इसका समाधान बेस ईयर को अपडेट करने पर झगड़ा करना नहीं है, बल्कि पहली तिमाही के अनुमानों की गणना उसी आधार पर करना है, जिस आधार पर पिछले साल की पहली तिमाही के अनुमान किए गए थे, और फिर उसकी तुलना करना है। संशोधन के प्रभाव को देखने के लिए ऐसा एक या दो बार किया जा सकता है। लेकिन इसे हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता।

मौजूदा विवाद का दूसरा मुद्दा "डिफ्लेटर" के इस्तेमाल को लेकर है। ये शब्द सुनने में सरल लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे जटिल गणनाएं होती हैं। अलग-अलग चरणों और आंकड़ों के अलग-अलग स्तरों पर डिफ्लेटर और डिफ्लेशन का इस्तेमाल किया जाता है।

डिफ्लेशन एक सरल प्रक्रिया है, जिसमें किसी वर्ष के आंकड़े को महंगाई की दर (इन्फ्लेशन रेट) के हिसाब से कम (डिफ्लेट) किया जाता है। ऐसा वास्तविक बदलाव का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। आर्थिक मूल्य कुछ इकाइयों के रूप में होते हैं, और ज्यादातर मामलों में पैसे के रूप में। इसलिए अर्थशास्त्री यह बताते हैं कि कोई आंकड़ा मौजूदा कीमत (करैंट प्राइस) के हिसाब से है या स्थिर कीमत (कॉन्स्टैंट प्राइस) के हिसाब से।

स्थिर कीमत वाले आंकड़े मौजूदा स्तर से संबंधित महंगाई के स्तर को घटाकर निकाले जाते हैं। डिफ्लेटर के इस्तेमाल को लेकर लगभग हमेशा विवाद रहता है। सवाल उठते हैं कि इसका प्रभाव अधिक क्यों रखा गया या कम क्यों। डिफ्लेटर तैयार करते समय महंगाई की दरों के साथ इसके तालमेल को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं।

नवीनतम जीडीपी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, कि स्थिर कीमत का सही मूल्य निकालने के लिए इस्तेमाल किए गए डिफ्लेशन फैक्टर कितने सही हैं। इसके अलावा, डिफ्लेशन फैक्टर का इस्तेमाल आंकड़ों के अलग-अलग स्तरों पर किया जाता है और इसलिए इनका सही और उचित होना भी जरूरी है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में एकरूपता होनी चाहिए। हिसाब-किताब या ढांचे में विरोधाभास होने पर पूरा अनुमान गलत हो सकता है।

अच्छी बात यह है कि विवादों में छिपे हुए मुद्दे सामने आते हैं, जो अन्यथा दिखाई नहीं देते या दबे रह जाते हैं। इस मामले में भी आंकड़ों पर उठाए गए सवालों से यह बात सामने आई है कि संबंधित आंकड़ों में किस आधार पर और कितनी बढ़ोतरी या कमी की गई है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और अब एक पब्लिक इन्टलैक्चुअल, अमर्त्य सेन ने "द आर्ग्युमेंटेटिव इंडियन" नामक पुस्तक लिखी थी। उनका कहना था कि भारत मूल रूप से ऐसा समाज है, जिसमें तर्क-वितर्क करने की प्रवृत्ति है। अच्छी बात है कि हम बहस करते हैं, क्योंकि इससे छिपी हुई कमियां और समस्याएं सामने आती हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908